(ii) RISING OF RIVERS GANGA AND GHAGRA IN U.P. AND FLOODS IN WEST BENGAL, BIHAR, DELHI, HARYANA AND RAJASTHAN

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बाढ़ के विषय को उठाने का अवसर दिया है। बाढ़ें हमारे देश में वर्षानुवर्ष से आ रही हैं। समाचारपत्रों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सभी बाढ़ों से ग्रस्त है। बाढ़ें दो प्रकार की होती हैं। एक तो अधिक वर्षा के कारण आती हैं और दूसरी वे होती हैं जो आदमियों के द्वारा लाई जाती हैं। आप छतौनी बांध के किस्से को लें। बलिया में वर्षानुवर्ष से इस बांध को बनाया जाता है, यह कटता है, फिर इसकी मरम्मत कर दी जाती है, फिर कटता है और फिर इसको बना दिया जाता है। इसी तरह से और भी कितने ही स्थान हैं जहां ड्रेनेज गलत रखे गए है। इसके कारण से वाटर लागिंग भी होता है।

दिल्ली और हरियाणा का झगड़ा चल रहा है ड्रेनेज के बारे में। उस गलत ड्रेनेज की वजह से दिल्ली के दो सौ गांव बाढ़ के कारण डूबे हुए है। ढांसा बांध कट रहा है। उसको इंजीनियर्ज बना नहीं पा रहे हैं। अन्ततोगत्वा सेना को बुलाया गया है बनाने के लिए। सारे उत्तर भारत में बाढ़ों की विभीषिका उपस्थित हो गई है। इसका कोई स्थायी उपाय आज तक खोजा नहीं गया है। क्या वर्षानुवर्ष करोड़ों रुपया सरकार इसी तरह से खर्च करती चली जाएगी ? क्या बाढ़ के समय नावों को चला देना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना, उनको खिला-पिला देना और जब बाढ़ का प्रकोप खत्म हो जाए तो उनको वापिस भेज देना यही इसका स्थायी समाधान है ? आज आवश्यकता इस बात की है कि इनको रोकथाम का कोई लांग रेंज प्लान सरकार बनाए। मोशन जो मैंने दिया है उसके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन के सामने स्थिति को स्पष्ट करें। बाढ़ की विभीषिका से देश को बचाने के लिए लांग रेंज प्लान चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि एग्रिकलचर मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं। दो मंत्री मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

जौनपुर की स्थिति को आप देखें। वर्षानुवर्ष से जौनपुर में बाढ़ आती है। बहुत भयंकर बाढ़ आती है। गोमती में आती है। उसकी वजह से शहर के मकानों की पहली स्टोरी पानी के नीचे आ जाती है। उसकी बहुत ही दुर्दशा होती है। यह चलती रहती हैं गर्मी के मौसम तक और तब तक चलती रहती हैं जब तक सारी सफाई नहीं हो जाती है। करोड़ों रुपया इसमें प्रतिवर्ष वेस्ट होता है। इस वास्ते दोनों तरह की शार्ट और लांग रेंज स्कीम्ज बननी चाहिये। यह विषय इतना बड़ा है कि आप मुझे मुश्किल से इसके लिए पांच मिनट ही देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट भी नहीं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : कुछ उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बलिया जनपद का जहां तक सवाल है गंगा नदी ने उसको घेर रखा है। चारों ओर से उसको गंगा और घाघरा ने घेर रखा है। इन दोनों के बीच में बलिया बसा है। जिस समय दोनों नदिपों में बाढ़ आ जाती है तो केवल शीट आफ वाटर ही दिखाई देता है नथिंग एल्स। बलिया का एक बलिया बैरिया बांध है। वह वर्षानुवर्ष से कट रहा है और कटान बराबर चलती रहती है। उससे लाखों एकड़ की फसल नष्ट होती है। जब उत्तर प्रदेश में इरिगेशन कमीशन था तो मुझको उसके साथ वहां जा कर देखने का अवसर मिला था। वहां हालत यह है कि आप सामान उस नदी में डालते जाते हैं लेकिन

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

कटान को आप रोक नहीं पाते हैं। इसी के साथ साथ दवाबा का इलाका है। बाघरा से आजमगढ़ का हिस्सा डूबा है और अयोध्या से लेकर सारा इलाका डूबा हुआ है, बल्कि कतरनियाघाट से शुरू किया जाय वह भी डूबा हुआ है। तो इसकी रोकथाम होना आवश्यक है। एक ओर जहां इस बात की आवश्यकता है कि इमीडियेट रिलीफ प्रोवाइड की जाय वहां लोग टर्म प्लानिंग भी जरूरी है। आज कलकत्ते जैसे शहर में बैरकपुर में नावें चल रही हैं। जब वहां नाव चलने की हालत हो जायेगी तो आखिरफ्लड कन्ट्रोल बोर्ड ने क्या किया? और इसका नतीजा यह होगा कि हमारे खाद्यान्न के ऊपर असर पड़ेगा। खरीफ की फसल उत्तर भारत में नष्ट हो रही है। और जौनपुर की स्थिति यह है कि अगर वहां मक्का की फसल और धान की फसल गई तो अकाल का सामना करना पड़ेगा। उस समय सरकार कहेगी हम तात्कालिक सहायता दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह स्थिति आने क्यों दी जाये? क्यों नहीं प्री-प्लान किया जाय। 30 वर्ष से सरकार ने क्या किया? मैं जनता सरकार को दोष नहीं देता, लेकिन खाली घाव पर मरहम पट्टी करने से काम नहीं चलेगा। घाव न हो इस पर विचारविमर्श होना चाहिये। इसलिये जिस समस्या के अन्दर उत्तर भारत का तीन चौथाई वर्ग प्रभावित है और चारे का नुकसान हो रहा है मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जाये और अच्छा हो कि इस सदन के उठने के पहले संबंधित मंत्री महोदय अपना सारा वक्तव्य सदन की मेज पर रखें जिस से सारे लोगों को अपने विचार सामने रखने का अवसर मिले और उसके आधार पर एक परमानेंट योजना बाढ़ से बचने की बनायी जाय।

Mr. Deputy-Speaker : Mr. Poojary.

श्री डी० जी० गवई (बलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में शैडयूल्ड कास्टस और ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो चर्चा हो रही है वह हर रोज डिसकंटीन्यू हो रही है। उसको रेगूलर चालू रखा जाय। देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. We are on matters under rule 377. This is not the way. Please take your seat. I will not allow this kind of interruption and disturbance in the procedure of the House. We are not on that discussion at all. You just get up on a point of order and start raising this. This is very bad.

Mr. Poojari.

(iii) HAVOC CAUSED BY RECENT FLOODS IN MANGALORE CITY AND MANGALORE TALUK.

SHRI P. JANARDHANA POOJARY (Mangalore): With your permission, I am bringing to the kind notice of the House....

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not going to allow any other Member to stand on his legs. I have called Mr. Poojary.

SHRI JANARDHANA POOJARY: With your permission, Sir, under rule 377, I am bringing to the kind notice of the House the sorrowful saga of the people of the Mangalore city and the Mangalore taluk who have faced the havoc caused by the recent floods following incessant and torrential rains. About 1,100 people have been rendered homeless, about 160 to 175 houses have been damaged, and 40 houses have been completely destroyed. Most of these houses belonged to the Harijans and other weaker sections of the society. The estimated damage to the property, apart from the crops, is about Rs. 5 to 7 lakhs. At this juncture I am also submit that, in Kumta and Honnavur, about 500 to 750 houses have been damaged; hundreds of acres were under flood waters and the standing crops have been damaged. The damage estimated is Rs. 1 crore.

The country is passing through a critical situation. The people have lost their houses, they have lost their clothes, they have lost their shelter, they have lost their belongings, and have lost their essential commodities. Under these circumstances, Government should not sleep over this situation. I would like to ask whether the Government is considering the helplessness and misery of the people, whether the Government will come out with a